जी20 अर्थव्यवस्था में भारत सबसे आगे

ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के शीर्ष नेताओं ने आर्थिक सुधारों, दीर्घकालिक नीतियों की सराहना की

नई दिल्ली 9 जुलाई ,आर्थिक सुधारों, निवेश-अनुकूल नीतियों और तेज़ विकास दर के दम पर भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख उद्योगपतियों और कॉरपोरेट नेताओं ने भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना करते हुए कहा है कि देश पिछले पांच वर्षों से लगभग आठ प्रतिशत की औसत विकास दर के साथ जी20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है.

उनका मानना है कि संरचनात्मक सुधारों, तकनीकी प्रगति और दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना दिया है.

एएनजेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुनो माटोस ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए हैं, जिनका सकारात्मक असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. उनके अनुसार, देश तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे भविष्य के क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हुआ है. उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत की विकास दर करीब आठ प्रतिशत रही है, जो जी20 देशों में सबसे अधिक है.

> ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर ने कहा कि भारत में दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण और निवेश समर्थक नीतियों ने विदेशी निवेशकों का विश्वास मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अपनी पूर्व बैठकों में उन्हें यह महसूस हुआ कि सरकार व्यापार और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझती है. उनके अनुसार, स्थिर नीतिगत माहौल और भविष्य की स्पष्ट आर्थिक रणनीति निवेशकों को भरोसा देती है, जिससे भारत में पूंजी निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

चार दिन में चांदी 15,000 टूटी, सोना भी फिसला

नई दिल्ली 9 जुलाई. वैश्विक अनिश्चितताओं और निवेशकों की सतर्कता के बीच घरेलू वायदा बाजार में सोना और चांदी लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी 2,000 रुपये यानी लगभग एक प्रतिशत टूटकर 2,21,502 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. पिछले चार कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत में करीब 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना 610 रुपये टूटकर 1,43,101 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई व ब्याज दरों को लेकर बढ़ी चिंताओं का असर कीमती धातुओं के बाजार पर देखने को मिला.

आईटी गिरावट ने बढ़ाया बड़ा निवेश

भारी बिकवाली के बीच अधिकांश निवेशक अपना रहे सतर्क रुख

मजबूत कैश फ्लो और स्थिर बिजनेस लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न

मुंबई 9 जुलाई, आईटी सेक्टर में पिछले छह महीनों से जारी भारी बिकवाली के बीच जहां अधिकांश निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं, वहीं देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम, पराग पारिख फ्लेक्सीकैप फंड, ने उल्टा दांव खेलते हुए प्रमुख आईटी कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाया है.

लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले इस फंड ने जून महीने में टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं. यह खरीदारी ऐसे समय में हुई है जब तीनों कंपनियों के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 40 से 55 प्रतिशत तक नीचे कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी पिछले छह महीनों में 25 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है. फंड के मासिक पोर्टफोलियो के अनुसार, जून में इंफोसिस के 54 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदकर कुल हिस्सेदारी 4.27 करोड़ शेयर कर दी गई.

> हालांकि, पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड के मुख्य निवेश अधिकारी एवं निदेशक राजीव ठक्कर का मानना है कि निवेश का आधार अल्पकालिक बाजार धारणा नहीं, बल्कि कंपनियों की मजबूत नकदी प्रवाह क्षमता है. उनके अनुसार, भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिकी डॉलर में राजस्व अर्जित करती हैं, जबकि उनके अधिकांश परिचालन खर्च रुपये में होते हैं. यदि वेतन वृद्धि नियंत्रित रहती है तो इन कंपनियों के मार्जिन और लाभप्रदता में सुधार की संभावना है.

विज्ञापनों के भ्रामक दावों पर एफएसएसएआई सख्त

नई दिल्ली 9 जुलाई, देश में खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और विज्ञापनों में किए जा रहे दावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है. नियामक संस्था ने लोट्टे इंडिया, फर्न्स एन पेटल्स और कुबेरा फूड्स सहित कई कंपनियों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

एफएसएसएआई का आरोप है कि कुछ उत्पादों पर '100 प्रतिशत प्राकृतिक', '100 प्रतिशत शाकाहारी' और 'प्रीमियम चॉकलेट' जैसे दावे किए गए, जबकि उत्पादों की वास्तविक सामग्री और लेबलिंग इन दावों के अनुरूप नहीं पाई गई. संस्था ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एफएसएसएआई के अनुसार, जांच के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं. लोट्टे इंडिया के कुछ उत्पादों पर पुराने प्रिंटेड लेबल का उपयोग बिना अनुमति के किया गया. 'लोट्टे चॉको पाय' पर '100 प्रतिशत शाकाहारी' का दावा भ्रामक पाया गया.

पहली छमाही में एनसीआर में मकानों की बिक्री 7 फीसदी घटी

नयी दिल्ली, 09 जुलाई देश के आठ प्रमुख आवासीय बाजारों में इस साल की पहली छमाही में घरों की बिक्री में एक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी.नाइट फ्रैंक ने मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता के आंकड़ों के आधार पर गुरुवार को जारी इंडिया रियल एस्टेट रिपोर्ट में बताया कि जनवरी-जून 2026 के दौरान इन आठ शहरों में 1,71,471 आवासीय इकाइयों की बिक्री दर्ज की गयी जो पिछले साल की पहली छमाही में बिके 1,70,201 घरों की तुलना में एक प्रतिशत अधिक है. साथ ही यह पिछले 12 साल की सबसे मजबूत अर्धवार्षिक बिक्री में से एक है.

वैकल्पिक ईंधन वाहनों को परमिट राहत

कमर्शियल वाहनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान

यह सुविधा निजी वाहनों पर लागू नहीं होगी

नई दिल्ली 9 जुलाई, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लागू परमिट छूट की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है.

साथ ही पहली बार एथेनॉल, मेथेनॉल और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों से संचालित कमर्शियल वाहनों को भी इस सुविधा के दायरे में शामिल किया गया है. इस फैसले का उद्देश्य कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बढ़ावा देना, परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाना और ऑपरेटरों के लिए नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना है.

देश में टैक्सी, बस, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों को विभिन्न राज्यों में संचालन के लिए नेशनल परमिट या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जैसी अनुमतियों की आवश्यकता होती है. इन परमिटों के लिए आवेदन, दस्तावेजों की जांच और निर्धारित शुल्क जैसी कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं. नई व्यवस्था के तहत पात्र इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को इन प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी.

> सरकार का मानना है कि यदि पर्यावरण अनुकूल वाहनों के लिए नियमों को सरल बनाया जाए तो इनके उपयोग में तेजी आएगी. परिवहन क्षेत्र देश के कुल कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है. ऐसे में इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथेनॉल और हाइड्रोजन आधारित वाहनों को प्रोत्साहन देने से प्रदूषण कम करने के साथ-साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी घटाई जा सकेगी. यह कदम ग्रीन मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

निसान ने दुनिया के लिए पेश की भारत में बनी नयी टेकटॉन

नयी दिल्ली, 09 जुलाई जापानी कार निर्माता कंपनी निसान मोटर की भारतीय इकाई निसान मोटर इंडिया ने गुरुवार को भारत में आयोजित विश्व प्रीमियर के दौरान नयी निसान टेकटॉन बाजार में पेश की.

इस साल भारत में पेश किया गया यह निसान का दूसरा नया मॉडल है. यह दो इंजन विकल्पों टर्बो टी160 औ टर्बो टी280 में उपलब्ध है. टी160 की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये और टी280 की शुरुआती कीमत 14.99 लाख रुपये रखी गयी है. कंपनी के अनुसार, यह अपने सेगमेंट की पहली एसयूवी है जिसमें पूरी रेंज में केवल टर्बोचार्ज्ड इंजन दिये गये हैं.

टेकटॉन का निर्माण चेन्नई स्थित निसान प्लांट में किया जायेगा. इसे 'एक कार, एक दुनिया' रणनीति के तहत विकसित किया गया है और भारत के अलावा मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किया जायेगा.

निसान मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक सौरभ वत्स ने कहा कि टेकटॉन भारतीय ग्राहकों को प्रीमियम डिजाइन, अत्याधुनिक तकनीक, शानदार प्रदर्शन और रोजमर्रा की उपयोगिता प्रदान करेगी.

इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म

नई दिल्ली 9 जुलाई, देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी समाप्त करने का फैसला किया है. इस निर्णय के तहत डिस्प्ले मॉड्यूल और वायरलेस चार्जिंग सिस्टम के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले चुनिंदा आयातित पुर्जों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है.

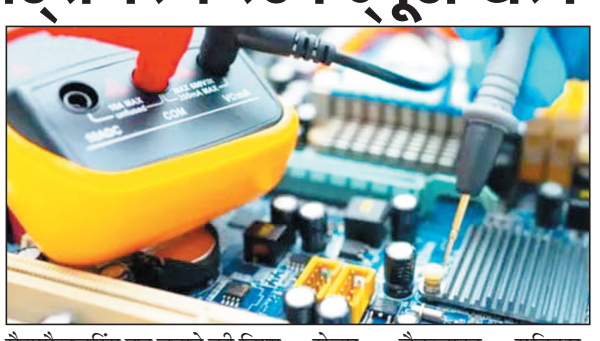

सरकार का मानना है कि इससे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत कम होगी, स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में गति मिलेगी. यह राहत 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, जिससे कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश और उत्पादन योजनाएं बनाने में सुविधा होगी.

नई व्यवस्था के तहत डिस्प्ले सेल्स, बैकलाइट यूनिट्स, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेंबली एनएफसी कॉइल्स और नियोडिमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट्स जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है.

साउथ इंडियन बैंक को मिला नया सीईओ

नई दिल्ली 9 जुलाई, निजी क्षेत्र के ऋणदाता साउथ इंडियन बैंक को नया नेतृत्व मिलने का रास्ता साफ हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महेश मुरलीधर पाई की बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

यह नियुक्ति 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल तीन वर्षों का रहेगा. बैंक ने नियामकीय फाइलिंग के माध्यम से इस मंजूरी की जानकारी दी है. अब इस प्रस्ताव को 16 जुलाई को होने वाली बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद इसे शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.

बैंक के अनुसार, आरबीआई ने 7 जुलाई 2026 को जारी अपने पत्र में महेश मुरलीधर पाई की नियुक्ति को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है. नियामकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह बैंक की कमान संभालेंगे.

बढ़त के साथ बंद हुए भारतीय शेयर बाजार

238 अंक से आगे रहा सेंसेक्स

80 .75 अंक चढ़ा निफ्टी

मुंबइ 9 जुलाई, घरेलू शेयर बाजार ने गुरुवार को सकारात्मक रुख के साथ कारोबार समाप्त किया. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन निवेशकों की खरीदारी के दम पर प्रमुख सूचकांक बढ़त दर्ज करने में सफल रहे.

कारोबार के अंत में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 238.22 अंक की मजबूती के साथ 76,741.82 अंक पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 80.75 अंक चढ़कर 23,962.80 अंक पर पहुंच गया. दिनभर के कारोबार के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अंतिम सत्र में चुनिंदा शेयरों में खरीदारी बढ़ने से प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद हुए.

> सेंसेक्स और निफ्टी में आई इस बढ़त ने हाल के कारोबारी सत्रों में बनी अस्थिरता के बीच निवेशकों को कुछ राहत दी है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले कारोबारी सत्रों में कंपनियों के तिमाही नतीजे, वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम, विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और अंतरराष्ट्रीय बाजारों का रुख घरेलू शेयर बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

समाचार विशेष

फेरबदल क्या अब सत्र के बाद!

नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार में फेरबदल का मामला बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गई है. पक ही नहीं रही है. पिछले एक साल से ज्यादा समय से मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा चल रही है. पिछले साल जून में सरकार के एक साल पूरे होने पर बदलाव की चर्चा शुरू हुई थी और इस साल जून बीतने के बाद भी चर्चा जारी है.

अब कहा जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र के बाद सरकार में फेरबदल होगी. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मई में मंत्रिपरिषद की बैठक की थी. उसके बाद जून में सचिवों के साथ बैठक की. एनडीए की तीसरी सरकार के दो साल और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 12 साल का जश्न मनाया गया. अब अक्टूबर में उनके सत्ता में आने के 25 साल पूरे होंगे तो उसकी रजत जयंती का जश्न पूरे देश में मनाया जाएगा. गौरतलब है कि वे अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे. सो, सारे जश्न होंगे और ऐसे हर मौके से पहले चर्चा होगी कि इसके बाद मंत्रिमंडल बदला जाएगा. इन चर्चाओं में दिन, महीने, साल गुजरते जा रहे हैं.

असल में प्रधानमंत्री मोदी छह से 11 जुलाई तक तीन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं. वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे. चार दशक के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जा रहा है.

> **मोदी संसद सत्र तक पुराने मंत्रियों को रखना चाहते हैं**
>
> जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि संसद के मानसून सत्र में वे नए मंत्रियों को विपक्ष के सामने उतारें. ध्यान रहे मानसून सत्र में सरकार कई ऐसे विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिनको लेकर विवाद चल रहा है. संविधान के 130वें और 131वें संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं. इसके अलावा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने और परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सरकार बैकफुट पर है.

तेलंगाना में पीआरसी पर सियासत तेज

हैदराबाद. ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएम आईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को तेलंगाना सरकार से गरीबों को तत्काल स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि कई गरीबों के पास दस्तावेज नहीं हैं और चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से बाहर होने का खतरा है.

हैदराबाद के सांसद ने सवाल उठाया कि आखिर राज्य सरकार पीआरसी जारी करने में क्यों देरी कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर सत्ताधारी दल को यह एहसास नहीं है कि तेलंगाना के गरीबों के पास दस्तावेज नहीं हैं, तो वह वास्तविकता से पूरी तरह कटी हुई है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

सांसद ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में जन्मे और जिनके नाम, या उनके माता-पिता और दादा-दादी के नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें पीआरसी (पर्सनल सर्टिफिकेट) जारी की जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति राज्य के शिक्षण संस्थानों में लगातार चार वर्षों तक अध्ययन करता है, तो वह राज्य में शिक्षा और रोजगार के लिए पात्र हो जाता है. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार पीआरसी जारी करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड और राजस्व रिकॉर्ड को आधार बनाए.

अलग ही पॉलिटिक्स खेल रहे थलपति विजय

नई दिल्ली. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को अगर आप सियासत के कच्चे खिलाड़ी समझ रहे हैं तो यह आपकी भूल है. वह अन्य विपक्षी दलों की राह पर न चलकर एकदम नई तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं.

हर नफा-नुकसान का हिसाब लगाकर फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं. थलपति न ज्यादा दोस्ती न ज्यादा बैर के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं. जी हां थलपति विजय अन्य विपक्षी दलों की राजनीति से बिल्कुल अलग तरह की सियासत खेल रहे हैं. उनकी राजनीति में बीजेपी का विरोध जरूर देखा जा रहा है लेकिन पीएम मोदी और केंद्र सरकार के साथ तालमेल भी देखा जा रहा है.

थलपति विजय ने राजनीति में जैसे ही कदम रखा, तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर दी. 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बार-बार क्क्ष्क्क्र पर सत्ता को केंद्रित करने, हिंदी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति थोपने और तमिलनाडु के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेने से बचते नजर आए. थलपति विजय ने वैचारिक और नीतिगत मुद्दों पर बीजेपी का विरोध जारी रखते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ तालमेल लगातार बढ़ाए रखा है.

> **थलपति विजय की राजनीति अलग कैसे**
>
> उनकी सरकार ने भाजपा के प्रति अपने वैचारिक विरोध को कमजोर नहीं किया है. वह तीन-भाषा नीति को अस्वीकार करती है, शिक्षा निधि को नई नीति से जोड़ने का विरोध करती है, और संघवाद और राज्य स्वायत्तता पर तमिलनाडु के पारंपरिक रुख को बरकरार रखती है. जो बदला है, वह मोदी सरकार के साथ संवाद का तरीका है. विजय ने नई दिल्ली के साथ बातचीत कम करने के बजाय उसे बढ़ाने का विकल्प चुना है.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072
इंदौर शाखा: प्लॉट नंबर 4 एवं 5, शॉप नंबर 105, 107, 109, प्रथम मंजिल, शेखर सेंट्रल, पलासिया चौराहा, मनोरमागंज, ए.बी. रोड, इंदौर, म. प्र. -452001

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/ जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 00310001867/ इंदौर शाखा) अमित (ऋणी) पिंकी अमित (सह-ऋणी)	14-04-2026 & ₹ 12,82,112/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 56/3, प.ह. नंबर 59/117, प्लॉट नंबर 48, वार्ड नंबर 28, तहसील पीथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश 454775 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 66, पश्चिम - सड़क, उत्तर - प्लॉट नंबर 47, दक्षिण - प्लॉट नंबर 49.	₹ 10,92,000/-	₹ 1,09,200/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **13-08-2026 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। **2.** संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **14-08-2026 दोपहर: 03:00 बजे से 04:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है। **3.** जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी। **4.** डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। **5.** नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। **6.** इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। **7.** अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दीपक मालवीय (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है। **8.** बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋ णदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें। **9.** नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है। **10.** यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 10.07.2026
सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पश्चिम रेलवे
निविदा सूचना

Tender Notice No. W722-1-26-27-02 Date:- 07.07.2026. Name of work: रेलवे कॉलोनी दाहोद में रिप्लेसमेंट अकाउंट पर 20 टाइप-II क्वार्टर के निर्माण से संबंधित इलेक्ट्रिकल कार्य। सहायक परियोजना प्रबन्धक (बिजली), सी साइट, फ्रीलैंडगंज, दाहोद -389160। Approximate Cost of the work: 30,20,990/-. Date & time of Submission & opening of E-Tender: Submission Up to 15.00 Hrs. on **31.07.2026** and the tenders will be opened at 15.30 Hrs on the same day.The Tender Notice and documents uploaded on the website www.ireps.gov.in / E-Tenders / Works / IR Electrical by this office. **0138**

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

न्यायालय पंजीयक,लोक न्यास अनुभाग-मल्हारगंज क्षेत्र इन्दौर,म.प्र.

(कोर्ट रूम न. 104-105 प्रथम तल संयुक्त तहसील कार्यालय, सुपर कॉरिडोर पर रेल्वे ब्रिज के पास टीगरिया बाटशाह जिला इंदौर)
क्रमांक /लो. न्यास/मल्हारगंज/2026
इन्दौर, दिनांक 2/07/2026 - 524
:: उदघोषणा ::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक 'मेसर्स विशाल भगत चेरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता एफ.एच.236, स्कीम नम्बर 54, विजय नगर इंदौर म.प्र. द्वारा म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 5/-का चालान क्रमांक 051/9999999/0070/06/26/031611 दिनांक 23/06/2026 प्रस्तुत किया गया है। ट्रस्ट की चल सम्पत्ति 5,100/- (पांच हजार एक सौ रुपये मात्र) अचल सम्पत्ति निरंक है। अतः उपरोक्तानुसार जिस व्यक्ति/संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवस में मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। प्रकरण में पेशी दिनांक 24/07/2026 नियत की गई। बाद मियाद आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 02/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

पंजीयक लोक न्यास,
अनुभाग-मल्हारगंज, इन्दौर (म.प्र.)